के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले आठ औद्योगिक विकास केन्द्रों के संबंध में वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत अंश-पूंजी (साझेदारी) और देय ऋण राशि जारी की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी (औद्योगिक विकास केन्द्र निगम) ने अपना आवेदन पत्र भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय वित्त संस्थान को आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं और क्या योजना के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के लिए और अधिक औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए संस्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में छह विकास केन्द्रों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि खेड़ा, घिरोंगी, बोराई एवं सिल्लारा में स्थित विकास केन्द्रों के लिए इक्विटी की मंजूरी के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय वित्त संस्थानों द्वारा भागीदारी की सूचना अभी नहीं दी गई है। इन संस्थानों के साथ फरवरी, 1995 में सरकार ने योजना हेतु इनकी सक्रिय भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक आयोजित की थी। राज्यों के साथ परामर्श करके सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है। केन्द्रीय वित्त संस्थानों की लंबित भागीदारी के संबंध में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक परियोजना हेतु उनके समानुपातिक योगदान का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नही।

Protest against Government decision to sell cement plant

7327. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI V. NARAYANASAMY:
DR. BAPU KALDATE:
SHRI RAMJI LAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a group of Ministers have recommended to put 11 Units of Cement Corporation of India for sale and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government have received memoranda from Associations/unions of Cement Corporation of india, Charkhi Dadri Unit, protesting against the sale of the Unit; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Since CCI has been continuously incurring heavy loses, various remedial measures were considered by the Govt. The feasibility of selling individual units has been one such step considered by the Govt.

(b) and (c) Certain representations/ memoranda have been received from the Associations/unions of Charkhi Dadri Cement Factory of CCI against the sale of the Unit. However, no final decision has been taken by the Govt. so far to sell off any individual unit of CCI.